इकाई 11 वर्ग, सत्ता और असमानता*

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्देश्य

11.1 प्रस्तावना

11.2 वर्ग बोधः प्रासंगिकता और निहितार्थ

11.3 कृषि वर्ग संरचना और वर्ग संबंधः एक ऐतिहासिक अवलोकन

- 11.3.1 औपनिवेशिक भूमि नीति और कृषि असमानता
- 11.3.2 राष्ट्रवादी दृष्टिकोणः औपनिवेशिक नीति का जवाब
- 11.3.3 उत्तर स्वाधीनता कृषि सुधार और वर्ग संरचना

11.4 नगरीय भारत में वर्ग भिन्नताएँ

- 11.4.1 सामाजिक वर्गों के प्रकार

11.5 प्रभुत्व वर्ग मॉडल : असमानता और परिवर्तन

- 11.5.1 संकल्पनात्मक ढांचा
- 11.5.2 एक नवीन संकल्पनात्मक ढांचाः निरंतरता और बदलाव

11.7 सारांश

11.8 संदर्भ

11.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

11.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आपके द्वारा संभव होगा :

- वर्ग की प्रासंगिकता और अर्थ की व्याख्या करना।
- वर्ग, शक्ति और असमानता के मध्य संबंध पर चर्चा करना।
- भारत में कृषि और नगरीय दोनों संदर्भों में वर्ग संरचना और आर्थिक असमानता का अवलोकन प्रदान करना।
- भारतीय संदर्भ में वर्ग के विश्लेषण और समझ में बदलाव और निरंतरता का वर्णन करना।

11.1 प्रस्तावना

भारत मुख्य रूप से लोकप्रिय सोच और शैक्षणिक क्षेत्रों में एक जाति समाज के रूप में माना जाता है। हालांकि भारत को केवल जाति की खिड़कियों के माध्यम से देखना अधूरा है। वर्ग भारतीय समाजिक वास्तविकता में अंतर्निहित विभाजन और असमानता को समझने में एक महत्वपूर्ण धुरी है। जिसको खंड 11.2 में वर्णित किया गया है।

निम्नलिखित दो भाग भारत को एक वर्ग समाज के रूप में दर्शाते हैं। यह ग्रामीण और शहरी भारत में वर्ग संरचना और वर्ग संबंधों के अध्ययन पर केन्द्रित है।

*कनिका कक्कर, दिल्ली विश्वविद्यालय।

भाग 11.5 प्रभुत्व वर्ग से संबंधित है, और इसकी सीमाओं को बताता है कि कहाँ तक यह शक्ति और प्रभाव का प्रयोग राज्य, चुनावी लोकतंत्र के मध्य करता है, वर्ग की आय और धन संबंधी असमानताओं के पुनःउत्पादन में योगदान देता है।

11.2 वर्ग बोधः प्रासंगिकता और निहितार्थ

भारतीय समाज एक अत्यधिक स्तरीकृत समाज है। कई धुरियाँ हैं जो भारतीय समाज के विभाजन और पदानुक्रम में योगदान करती हैं; जिनमें जाति और वर्ग आधारभूत है। सामान्य प्रवृत्ति भारत को आमतौर पर जाति समाज के रूप में अध्ययन करने की रही है। हालांकि, भारतीय समाज में वर्ग,सत्ता और असमानता का एक महत्वपूर्ण आधार है और इसलिए, चिंतन की आवश्यकता है।

वर्ग स्तरीकरण की एक व्यवस्था है जो जाति के विपरीत चरित्र में आर्थिक है, जाति समाज के आनुष्ठानिक क्रम से संबन्धित है। एक वर्ग व्यवसाय, जमीन के मालिकाना हक, बाजार की उपज या अवषिष्ट आय और सामाजिक पूंजी जैसे कसौटियों पर आधारित है। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये सभी मानदंड सीधे पैसे में परिवर्तनीय हैं इसलिए, धन या सम्पत्ति वर्ग स्तरीकरण में केंद्रीय पहलू है। हालांकि, जाति के विपरीत वर्ग व्यवस्था लचीली और कम कठोर है। जबकि जाति प्रस्थिति जन्म के समय तय होती है और वंशानुगत रूप से पाई जाती है, वर्ग की प्रस्थिति धन या सम्पत्ति पर आधारित होती है, जो किसी व्यक्ति द्वारा अधिग्रहित या अर्जित की जाती है।

भारतीय समाज में स्तरीकरण और पद विवरण के आधार के रूप में जाति की तुलना में वर्ग का महत्व हाल ही में आया है। परम्परागत भारत में व्यावसायिक प्रस्थिति, जजमानी प्रणाली की व्यापकता के कारण वर्ग से भिन्न थी। पारंपरिक व्यावसायिक दायित्वों/ संरक्षक-ग्राहक (Patron-Client) संबंधों की जजमानी प्रणाली ने जातिगत श्रेणी को ढक रखा था और अपने पूर्वजों से प्राप्त पेशागत स्थिति को अपनाना व्यक्तियों के लिए आवश्यक कर दिया था। संवैधानिक प्रावधानों की जाति आधारति कठोरता को चुनौती भूमि सुधारों का आगमन, औद्योगिकीकरण, शिक्षा का प्रसार, अर्थव्यवस्था का मुद्रीकरण और आधुनिक परिवहन की उपलब्धता के कारण बाजार लेनदेन की व्यवहार्यता ने जजमानी व्यवस्था के लिए क्रमिक क्षरण को जन्म दिया है। वर्तमान संदर्भ में व्यक्ति अपनी व्यावसायिक योग्यता और कौशल के अनुसार, अपनी जाति से स्वतंत्र, अपने व्यवसाय का चयन करने के लिए कम या ज्यादा जरूर स्वतंत्र है। श्रीपुरम गाँव पर आंद्रे बेते का काम (1966) अच्छी तरह से दर्शाता है कि नई ताकतें सामाजिक स्तरीकरण के पारंपरिक तरीके को अस्त-व्यस्त रही हैं और आर्थिक वर्ग और राजनीतिक व्यवस्थाओं का निर्माण कर रही हैं जो अब पूरी तरह से जाति पर निर्भर नहीं हैं। किसी व्यक्ति की उच्च जाति प्रस्थिति उसके आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावी होने का संकेत नहीं देती है। हालाँकि, अब जजमानी जैसी व्यवस्था कमजोर हो गई है और जाति के साथ पेशे का जुड़ाव भी कम हो गया है, परन्तु यह पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है। अभी भी कुछ व्यवसाय जातियों से जुड़े हुए हैं। कई कृषि मजदूर और सफाई व्यवस्था के काम में लगे लोग निम्न जातियों से हैं, जैसे कुछ उच्च वेतन वाले व्यवसाय उच्च जातियों से जुड़े हैं।

बोध प्रश्न 1

i) रिक्त स्थानों को भरकर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें

क) ..... पारंपरिक व्यावसायिक दायित्वों संरक्षक-ग्राहक संबंधों की एक व्यवस्था है।

ख) किसी व्यक्ति की जाति प्रस्थिति जन्म और वंशानुगत रूप से निर्धारित की जाती है, इसके विपरीत उसकी वर्ग प्रस्थिति लचीली होती है जो सम्पत्ति/आय पर आधारित होती है और उसे ..... किया जा सकता है।

ग) भारतीय समाज में स्तरीकरण और पद वितरण के आधार के रूप में .... का महत्व हाल ही में आया है।

11.3 कृषि वर्ग संरचना और संबंधः एक ऐतिहासिक अवलोकन

यह भाग औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं को स्वतंत्रता के बाद कृषि सुधारों और वर्ग संरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि और असमानता पर एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।

11.3.1 औपनिवेशिक भूमि नीति और कृषि असमानता

विद्वत्तापूर्ण कार्यों से संकेत मिलता है कि स्वतंत्रता के बाद के भारत में कृषि समाज में प्रचलित वर्ग आधारित असमानता और पदानुक्रम औपनिवेशिक सरकार की नीतियों और कार्य प्रणालियों का एक परिणाम हैं। पी.सी. जोशी (1967) ने कहा कि भारत की पूर्व-विद्रोह काल में कृषि नीति वैज्ञानिक-बौद्धिक समझ के बजाय औपनिवेशिक सरकार के राजनीतिक हित को दर्शाती थी।

रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट जिसे 1928 में नियुक्त किया गया था, अकाल आयोग, जो कृषि समस्या के प्रति केवल सहानुभूति दिखाता है, द्वारा प्रकाशित कई आधिकारिक पूर्व-विद्रोही दस्तावेजों के साथ निरंतरता थी। इसने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भू-स्वामित्व भूमि की किरायेदारी और भू-राजस्व का मूल्यांकन और सिंचाई शुल्क को छोड़ दिया। औपनिवेशिक राज्य की भूमि और कृषि नीति पूंजीवादी और जबरन वसूली की प्रवृत्ति को रेखांकित करती है, जो इन तथ्यों में दिखाई देती थीः

पहला, उच्च कर की मांग जो कृषि पर औपनिवेशिक राज्य ने कृषि पर जमींदारी और रैय्यतवारी' व्यवस्था का हिस्सा बनने पर की। ब्रिटिश के दावों के विपरीत, इसके वास्तविक भू-राजस्व संग्रह आम तौर पर अधिक थे उनकी तुलना में जो पारंपरिक स्वदेशी शासकों के अधीन थे।

बॉक्सः 11.1 जमींदारी और रैय्यतवारी व्यवस्था

जमींदारी व्यवस्था प्रणाली ने औपनिवेशिक राज्य के लिए जमींदारों के साथ स्थाई व्यवस्था को आवश्यक कर राजस्व दर को बहुत उच्च स्तर पर तय किया। जमींदार मध्यस्थ था राज्य और प्रत्यक्ष कृषक के बीच जो राज्य को निश्चित भू-राजस्व का भुगतान करते थे, जबकि उन्होंने वास्तविक उत्पादकों से किराया वसूल किया था। हालांकि, भू-राजस्व पहले से तय था, परन्तु औपनिवेशिक राज्य ने पाया कि यह समय के साथ होने वाली कृषि आय में वृद्धि से मेल नहीं खा रहा था। आय के अतिरिक्त भाग को बिचौलियों द्वारा बड़े पैमाने पर हथियाया जा रहा था।

नतीजतन, औपनिवेशिक सरकार की सीधे किसान, या रैयत के साथ बनाई गई अस्थायी व्यवस्था रयोतवारी प्रणाली में परिवर्तित हो गई। यह समय-समय पर संशोधन और राजस्व दरों को अधिकतम सीमा तक बदली जहाँ तक अर्थव्यवस्था या राज व्यवस्था सह सकती थी।

दूसरा, औपनिवेशिक शासन के दौरान जमींदारी प्रथा और भूमि वितरण अनियंत्रित थे। इसने किसानों को अपने और राज्य के बीच मध्यस्थों की श्रृंखला को बनाए रखने के लिए उच्च कर का भुगतान किया। किराए की मांग के अलावा, जमींदारों ने नकदी, कृपा या श्रम (भिखारी) के रूप मे में कई अवैध सुधारों का सहारा लिया, जिसने किसानों पर भारी बोझ डाला।

उपरोक्त संदर्भ के तहत, बड़े भूस्वामियों ने अपनी भूमि को किराये पर देना अधिक लाभदायक पाया, भूमिहीन किसानों से बहुत अधिक किराए और अन्य अवैध बकाए वसूले गए; बजाय बड़े पैमाने पर पूंजी गहन कृषि कार्य को अपनाने के। इसलिए, यह औपनिवेशिक भूमि नीति थी, जिसने पूंजीवादी खेती को उभरने नहीं दिया, ना कि कृषि वर्गों की किसी भी कथित जन्मजात सामंती 'मानसिकता कारण रही थी।

तीसरा, औपनिवेशिक राज्य और प्रभुत्वशाली वर्गों द्वारा किसानों पर भारी कर लगाने से उन पर निजी साहूकारों और जमींदारों का अत्यधिक ऋण हो गया। परिणामस्वरूप, बंधुआ श्रम देश के बड़े हिस्से में एक आम विशेषता बन गई।

इस प्रकार, औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय किसानों के एक बड़े वर्ग को संसाधनों की कमी थी और वे जीवन निर्वाह स्तर से लगभग नीचे रह रहे थे। ग्रामीण समाज के उच्च वर्गों ने पूंजीवादी कृषि की तुलना में किराए और सूदखोरी को आय का अधिक लाभदायक स्रोत पाया। परिणामस्वरूप उन्होंने कृषि को आधुनिक बनाने और सुधारने में बहुत कम रुचि ली। इसके अलावा, औपनिवेशिक राज्य ने भी निवेश नहीं किया था जो कृषि से बलपूर्वक प्राप्त हुआ था। इसलिए भारतीय कृषि पिछड़ी हुई रह गयी।

बॉक्सः 11.2 कृषि भारत में महिलाओं की आर्थिक अधीनताः एक औपनिवेशिक विरासत

कृषि अर्थव्यवस्था में औपनिवेशिक हस्तक्षेप ने प्रभावशाली भूस्वामी वर्गों के निकष्ट अत्याचारों को मजबूत किया, जो पितृसत्तात्मक प्रचलनों के और बदतर कर बेटियों की संकटग्रस्त बिक्री, महिला रैयतों के उत्पीड़न के अधिक बढ़ा दिया और वर्ग आधारित विवाह के मानदंडों और यौन नैतिकता की नियामक शक्ति में वृद्धि किया । इसके अलावा, औपनिवेशिक शासन ने पुरुषों के हाथों में व्यक्तिगत भूमि अधिकारों को निहित कर दिया, जो पूर्व-औपनिवेशिक कृषि संरचना में प्रचलित उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से महिलाओं के अपवर्जन को सुदृढ़ करते थे, जहां मातृवंशीय व्यवस्था मौजूद थी, वे धीरे-धीरे उत्तराधिकार के पितृवंशीय ढांचे में बदल गए।

स्वतंत्र भारत में भूमि/संपत्ति के अधिकार अभी भी अधिकांश ग्रामीण और शहरी महिलाओं के लिए भ्रांतिजनक हैं, इसके बावजूद, 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम को लागू करना पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान विरासत अधिकार सुनिश्चित करता है। वास्तव में कुछ महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति विरासत में मिलती है और अपने भाई से इस पर अपना अधिकार जताती है।

11.3.2 राष्ट्रवादी दृष्टिकोणः औपनिवेशिक नीति का प्रतिक्रिया

उपनिवेशवाद में उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध के बाद से राष्ट्रवादी भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के आलोचक थे। उन्होंने भूमि नियंत्रण के औपनिवेशिक सिद्धांत का वाद-विवाद करके खारिज किया, जिसमें विशेष रूप से औपनिवेशिक राज्य द्वारा एकत्र किए गए उच्च भू राजस्व और दमनकारी भूस्वामी -रैयतों के संबंधों में परिवर्तन के लिए बहस करने वाली

राजस्व प्रणाली शामिल है। प्रारंभिक राष्ट्रवादी, न्यायमूर्ति रानाडे और आर.सी. दत्ता ने औपनिवेशिक राज्य को संस्थागत संरचना, अर्थात् पारंपरिक भूमि संबंधों, जो कि आर्थिक पिछड़ेपन पर सीधा असर डालता है और जिसमें पुनर्गठन के लिए राज्य के प्रबल हस्तक्षेप की आवश्यकता है, की अनदेखी करने के लिए प्रश्न खड़ा किए । हालांकि रानाडे और दत्ता ने ग्रामीण गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन के लिए औपनिवेशिक राज्य की आलोचना की, लेकिन वे गाँव के लोगों की भूमि की स्थिति में सुधार के लिए पर्याप्त उपाय सुझाने में विफल रहे।

अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत बाद के राष्ट्रवादियों ने कृषि असमानता को हल करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किए । इस तरह अंबेडकर ने अपने कोठी-विरोधी आंदोलन के माध्यम से न केवल औपनिवेशिक राज्य का विरोध किया, बल्कि उच्च जाति की प्रभुत्व वाले भूस्वामित्ववाद का भी विरोध उसके उन्मूलन के लिए विधेयक की शुरुआत करते हुए किया । अंग्रेजों ने कोंकण क्षेत्र के इलाके में शक्तिशाली व्यक्तियों (कोठ) को अधिक शक्ति देकर कर भू-राजस्व को इकट्ठा करने के लिए कोठी प्रणाली की शुरुआत की थी। उन्होंने हमेशा कर जमा करने के लिए क्रूर और हिंसक साधनों का सहारा लिया।

कृषि असमानता के खिलाफ लड़ाई बीसवीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड गई। स्वंत्रोत्तर भारत में पेश किए गए ज्यादातर कृषि सुधार राष्ट्रवादी समाज के प्रति दमनकारी औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ राष्ट्रवादियों के अभियान का एक हिस्सा था। इस प्रकार, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया सविनय अवज्ञा अभियान (1930-40) देश के कई हिस्सों में ना-कर और ना-किराया (नो-टैक्स और नो रेंट) अभियान के रूप में लिया गया। किसानों के लिए महात्मा गांधी की चिंता उनकी टिप्पणी 'भूमि और सभी संपत्ति उनकी है जो इस पर काम करेंगे', से स्पष्ट रूप से सामने आती है, जो 1930 के दशक के अंत में की गयी। यह जोतने वालों की भूमि (Land to tiller) की धारणा का पर्याय था जो स्वतंत्रता के बाद के कृषि सुधारों के लिए मौलिक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, 1931 ने आर्थिक कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें किसान के मौलिक अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिनको स्वतंत्र भारत में पेश करना चाहते थे। कृषि सुधारों की मांग को दोहराते हुए कांग्रेस अधिवेशनों के साथ-साथ बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में किसान सम्मेलनों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन से ताकत और समर्थन हासिल करके, कृषि असमानता के खिलाफ किसान संघर्ष तेज हो गया और 1930-40 के दशक में देश के विभिन्न हिस्सों में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने की मांग करते हुए आक्रामक जमींदार विरोधी आंदोलनों का आकार ले लिया।

सोचें और करें 1

तेलंगाना और तेभागा किसान विरोध, औपनिवेशिक शासन के इशारे पर प्रभुत्वशाली कृषि वर्ग द्वारा पेश किए गए वर्ग और आर्थिक विषमताओं के विरोध की नींव रखते है जो स्वतंत्रता के बाद के कृषि सुधारों के लिए आधार बनाते हैं। दो पृष्ठों में विस्तृत व्याख्या करें।

11.3.3 उत्तर स्वाधीनता : कृषि सुधार और वर्ग संरचना

क) कृषि सुधारः प्रावधान और निहितार्थ

आजादी के बाद, कांग्रेस सरकार ने जे. कुमारप्पा की अध्यक्षता में कृषि सुधार समिति की नियुक्ति की, जिनकी सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित भूमि सुधार स्वतंत्र

भारत में पेश किए गए जो ग्रामीण आर्थिक विषमताओं को चुनौती देने के लिए महत्वपूर्ण थे।

i) जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, 1950 आजादी के बाद का सबसे बड़ा कृषि सुधार था। हालाँकि, यह अधिनियम 1951 में सरकार द्वारा प्रथम संशोधन अधिनियम जारी करने के बाद ही संविधान की धारा 31 (क), 31 (ख) और नौवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के बाद ही सही मायने में लागू किया जा सका, जिससे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था । संशोधन और परिवर्धन ने राज्य को किसी भी भूमि या संपत्ति का अधिग्रहण करने का अधिकार दिया।

ii) जमींदारी उन्मूलन अधिनियम ने भी बेगारी/बंधुआ मजदूरी को भी दंडनीय अपराध घोषित किया।

iii) राज्य और खेतिहर के बीच मध्यवर्ती स्वामित्व के उन्मूलन के लिए कानून ने, मिट्टी वास्तविक रूप से खेत को जोतने वाले को भूमि देने का अधिनियम 1950 में पारित किया और दूसरी पंचवर्शीय योजना द्वारा लागू किया गया था। कानून में विधवाओं, नाबालिगों और अन्य विकलांग व्यक्तियों को छोड़कर जमीन को पट्टे/भाड़े पर देने के लिए प्रतिबंधित है। भूस्वामी द्वारा बटाईदार और अन्य किरायेदारों को जबरन और अवैध निकासी से बचाने के लिए यह प्रावधान किए गए थे।

iv) भूमि अधिकतम सीमा निर्धारित अधिनियम 1960 में कानूनी रूप से अधिकतम आकार को निर्धारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था आय/संपत्ति के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए इससे ज्यादा कोई भी किसान या खेतिहर घराना कोई जमीन नहीं रख सकता था।

V) पुनः प्राप्त बंजर भूमि के विकास के लिए सामूहिक खेती के विचार, जिस पर भूमिहीन मजदूरों को रोजगार दिया जा सकता था, को प्रोत्साहित किया गया।

स्वतंत्रता के बाद शुरू किए गए भूमि सुधारों के कारण, बड़े भूस्वामियों के हाथों में भूमि की केन्द्रीकरण बढ़ गया है। मूलभूत प्रावधान, ''जोतने वालों की भूमि'' बड़े भूस्वामियों द्वारा विकृत कर दिया गया था, जिन्होंने कानून के लागू होने से पहले लंबी अवधि के किरायेदारों को बेदखल कर दिया था। इसके अलावा, भूमि अधिकतम सीमा निर्धारित अधिनियम के मूल उद्देश्यों को बड़े जमींदारों और अन्य निहित स्वार्थों द्वारा भूमि के काल्पनिक विभाजन या भूमिहीन और गरीब किसानों को भूमि का बेनामी लेनदेन के माध्यम से रिकॉर्ड में महज कागज प्रविष्टियों या सम्पत्ति के नकली मालिकाना के माध्यम से, विरासत का कानून और किसानों की निरक्षरता के कानून के साथ संघर्ष के कारण इसे प्रभावहीन बनाया गया।

इसके अलावा, संयुक्त खेती जैसे विचारों को थोड़ी सफलता मिली, क्योंकि इसका प्रयोग विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों द्वारा भूमि सुधारों की उपेक्षा की सुविधाजनक विधि के रूप में और सरकारी संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में प्रयोग किया गया था।

मेनचर (2002: 216-17) बताते हैं कि राज्य ने अपना ध्यान भूमि पुनर्वितरण से कृषि की उत्पादकता 'बढ़ाने पर केंद्रित कर दिया । कृषि के बढ़ते हुए निगमीकरण और व्यावसायीकरण ने भूमि समेकन, पूंजी प्रधान कृषि तकनीकों का उपयोग, एकल-फसल और निर्यात फसल उत्पादन का नेतृत्व किया। इसने मध्यम और छोटे किसानों और

भूमिहीन कृषि मजदूरों को बेरोजगार बना दिया है और उन्हें निकृष्टता की स्थिति में पहुंचा दिया। पूंजी प्रधान कृषि और ग्रामीण असमानताओं को बढ़ाने में इसके निहितार्थ पहली बार 1960 के दशक में भारतीय राज्य द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत के साथ दिखाई दिए। हरित क्रांति ने उच्च-उपज वाले किस्म (HYV) के बीज, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधा, कीटनाषक और उर्वरक जैसे आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी को अपनाया। इसके लिए भारी निवेश की आवश्यकता थी और इसे केवल बड़े भूस्वामियों और धनी किसानों द्वारा ही वहन किया जा सकता था। पी.सी. जोशी (1974)के अनुसार पंजाब और हरियाणा में जो प्रवृत्ति सामने आई, वह यह थी कि छोटे भूस्वामियों ने अपनी जमीन बड़े किसानों को किराए पर दे दी, जिन्हें अपनी मशीनरी का लाभकारी ढंग से उपयोग करने के लिए बड़ी जमीन की जरूरत थी। इसने बड़े जमींदारों को समृद्ध किया, इसने भूमिहीन श्रमिकों को दुख और बेरोजगारी में धकेल दिया।

सोचे और करें 2

भारत में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में वृद्धि कृषि वर्ग की असमानताओं और ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए राज्य की विफलता का प्रतिबिंब है। अपनी नोट बुक में इस मुद्दे पर अपने विचार प्रस्तुत करें।

ख) कृषक वर्ग संरचना और वर्ग संबंध

कृषक सामाजिक संरचना में क्षेत्रीय भिन्नताएँ होती है। प्रत्येक क्षेत्र में विविध समूह और वर्ग होते हैं जो भूमि के मामलों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के लिए कुछ पदों पर कब्जा कर लेते हैं। आजादी के बाद के भारत में पाए जाने वाले कृषि वर्गों को वर्गीकृत करने के लिए ए. आर. देसाई और डैनियल थॉर्न जैसे प्रमुख विद्वानों ने सामान्य रूपरेखा तैयार की है। ये रूपरेखा कृषि समाज में आय और धन/संपत्ति की पदानुक्रम को दर्शाती है, जो प्रचलित आर्थिक असमानता पर प्रकाश डालती है। भूमि सुधार, सहकारी और ऋण समितियों का उदय जमींदारों की शक्ति को कम करने में विफल रहा जैसा कि पहले भाग में देखा गया था।

ए.आर. देसाई (1959) कृषक सामाजिक संरचना की सबसे लोकप्रिय धारणाओं को बताते हैं, जिसमें चार वर्ग शामिल हैंः कृषि क्षेत्र में तीन वर्ग (कृषक की श्रेणी) का गठन भू-स्वामियों, जोतदारों और मजदूरों द्वारा किया जाता है, जबकि चौथा वर्ग गैरकृषक का है।

डैनियल थॉर्नर (1956) ने जमींदारों, जोतदारों और मजदूरों के रूप में खेती करने वालों के उपरोक्त वर्गीकरण को अस्वीकार कर दिया। उनके विचार में एक ही आदमी इन श्रेणियों के लिए एक साथ हो सकता है। एक व्यक्ति स्वयं कुछ एकड़ भूमि पर खेती कर सकता है, कुछ जमीन किराए पर दे सकता है, और आपातकाल में मजदूर के रूप में दूसरे के खेत पर काम कर सकता है। उन्होंने तीन विशिष्ट शब्दों का उपयोग करके कृषक संबंधों का विश्लेषण किया हैः

- कृषि जमींदारों के लिए मालिक,
- मालिकों की तुलना में भूमि में निम्न अधिकारों के साथ किसान (जोतदारों सहित) काम करने वाले कृषक (किरायेदारों सहित)
- खेतिहर मजदूरों के लिए मजदूर जो दूसरों की जमीनों/भूखंड पर काम करते हैं।

वह निम्न मानदंडों का उपयोग करके इस वर्गीकरण पर आए हैं :

i) स्वयं की खेती या मजदूरी या किराए के रूप में जमीन से प्राप्त आय।

ii) अधिकारों की प्रकृति अलग हो सकती है जैसा कि यह मालिकाना और स्वामित्व या जोरदारों या बटाईदारी के दावों से उत्पन्न हुई है।

iii) वास्तव में खेती में कार्य करते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं जो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं (गैरहाजिर), आंशिक काम करने वाले, परिवार श्रम के साथ सम्पूर्ण काम करने वाले वास्तविक खेतिहर, वे जो दूसरों के लिए काम करते हैं और मजदूरी करते हैं।

बोध प्रश्न 2

i) प्रारंभिक राष्ट्रवादी औपनिवेशिक कृषि नीति की आलोचना कैसे करते हैं? (3 वाक्यों में व्याख्या करें)

.....

.....

.....

.....

.....

ii) हरित क्रांति ने कृषि प्रधान भारत में विषमताओं को बढ़ाने में योगदान दिया। चर्चा करें (एक वाक्य में स्पष्ट करें)

.....

.....

.....

.....

.....

iii) डैनियल थॉर्नर की कृषि वर्गों के वर्गीकरण की गणना करें।

.....

.....

.....

.....

11.4 नगरीय भारत में वर्ग भेद

वर्ग असमानता और आय और धन का विभेदीकरण एक घटना है जो न केवल कृषि प्रधान भारत के लिए सच है। नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तरह ही व्यवसाय और आय आध ाारित भेद स्पष्ट हैं। इस प्रकार, नगरीय भारत के पूँजीपतियों और मजदूर वर्ग द्वारा दी गई आर्थिक भिन्नता और पदानुक्रमित स्थिति कृषि प्रधान समाज में जमींदारों और भूमिहीन मजदूरों के साथ काफी हद तक एक जैसी है। यह वर्ग-आधारित भेदों और विविधताओं के सार्वभौमिक चरित्र को पुष्ट करता है, जो हमें नगरीय वर्गों पर एक विस्तृत विस्तार करने

की आवश्यकता से छूट देता है। हालांकि, कृषि वर्गों के विपरीत, नगरीय क्षेत्रों में वर्ग गैर-कृषि रोजगार में कार्य करने से आय प्राप्त करते हैं। नतीजतन, नगरीय संदर्भ में सामाजिक वर्गों का एक संक्षिप्त अवलोकन आवश्यक है।

11.4.1 सामाजिक वर्गों के प्रकार

मोटे तौर पर, निम्नलिखित सामाजिक वर्ग नगरीय भारत के लिए विशिष्ट हैं:

औद्योगिक पूंजीपति वर्ग

यह वर्ग पहले से मौजूद व्यापारी वर्ग में से औपनिवेशिक शासन के दौरान विकसित हुआ। आर्थिक और सामाजिक रूप से यह सबसे मजबूत है। स्वतंत्रता के बाद, कृषि, उद्योग और व्यापार जैसे प्रमुख क्षेत्र निजी व्यक्तियों के लिए छोड़ दिए गए थे। राज्य द्वारा बुनियादी ढाँचे के निर्माण और भारी उद्योगों की स्थापना की गई। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के कारण पूंजीपतियों के स्वामित्व और नियंत्रण वाले उद्योगों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। टाटा और बिड़ला जैसे औद्योगिक व्यापारिक घराने संपत्ति संसाधन की सघनता दिखाते हुए, आजादी के बाद उभरे। लाभ की चाह और पूंजी संचय इस वर्ग का प्राथमिक लक्ष्य है। अपनी आर्थिक स्थिति के परिणामस्वरूप यह वर्ग राज्य पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है जैसा कि निम्नलिखित अनुभाग में जांच की गई है।

सफेदपोश श्रमिक वर्ग

वर्ग का गठन प्रशासनिक, प्रबंधकीय और अन्य सेवा संबंधी कार्यों में लगे सभी लोगों द्वारा किया जाता है। पेशेवर, प्रबंधक, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, नौकरशाह सफेदपोश कर्मी हैं। संक्षेप में, सफेद पोष श्रमिक वर्ग गैर-हस्तचालित और मानसिक श्रमिकों का वर्ग है। सफेद कॉलर वर्ग के सदस्यों की शैक्षिक अर्हता, तकनीकी योग्यता और विशेषज्ञता उन्हें नगरीय भारत में कुशल कार्यबल का हिस्सा बनाती है। यह वर्ग काम के लिए वेतन प्राप्त करता है और आर्थिक रूप से धनी है इसके सदस्य पदानुक्रम के उच्च और मध्य वर्ग का एक हिस्सा हो सकते हैं।

यह वर्ग ब्रिटिश शासन के दौरान उभरना शुरू हुआ क्योंकि आधुनिक उद्योग, कृषि, वाणिज्य, वित्त, प्रशासन, प्रेस और सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों का विस्तार उस समय हुआ था। स्वतंत्रोत्तर भारत में तेजी से औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और वैश्वीकरण ने उद्योगों, व्यापार और वाणिज्य, निर्माण, परिवहन और सेवा आदि में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए, इसी तरह, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक जटिल संस्थागत संरचना सहित एक विशाल नौकरशाही संरचना देश की लंबाई और चौड़ाई में निर्मित हुए । सफेदपोश वर्ग शायद ही एक सजातीय श्रेणी का गठन करता है। गैर-हस्तचालित श्रमिकों के इस गैर-मालिकाना वर्ग के भीतर, एक गहरी पदानुक्रम मौजूद है। शीर्ष पर कुछ उच्च भुगतान किए गए कर्मचारी संवर्ग हैं, जो आय पदानुक्रम के उच्च और मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और निचले तल पर उसे भुगतान किया जाता है जो एक अच्छी तरह से परिभाषित मध्यम वर्ग में निश्चित रूप नहीं पा पाये हैं। वे अपनी जीवन शैली में भी भिन्न होते हैं।

छोटे उद्यमी

इस वर्ग में छोटे व्यवसायी, व्यापारी और दुकानदार शामिल हैं। यह आधुनिक शहरों और कस्बों के विकास के साथ विकसित हुआ है। यह वस्तुओं और सामग्री उत्पादकों और आम उपभोक्ताओं के बीच की कड़ी का गठन करता है। इसके सदस्य अपने जीवन को मुनाफे

के अंतर की प्रक्रिया पर बनाते हैं जिस पर वे अपना माल खरीदते और बेचते हैं। स्वतंत्र भारत के बाद के शहरों में अभूतपूर्व वृद्धि ने इस वर्ग के बड़े पैमाने पर विकास को प्रेरित किया है। बढ़ती शहरी आबादी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं और सेवाओं के लिए मांग पैदा करती है। छोटी दुकानें, उद्यम और व्यापार इन जरूरतों को पूरा करता है। शहर के निवासियों और ग्रामीण प्रवासियों के पास, जिनके पास पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता की कमी है, उनका इसलिए संगठित क्षेत्र में प्रवेश बंद है, जो छोटे पैमाने पर उत्पादन इकाइयों या छोटे व्यवसायों की स्थापना करते हैं। इनका पैमाना आमतौर पर छोटा होता है, जिसमें न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इनमें से अधिकांश इकाइयां और व्यवसाय घर-आधारित उद्यमों के रूप में चलाए जाते हैं।

श्रमिक वर्ग

नगरीय भारत में श्रमिक वर्ग का गठन हाथ से काम करने वाले और नीलापोश श्रमिकों द्वारा किया जाता है जो अर्ध-कुशल और अकुशल नौकरियाँ करते हैं। मजदूर वर्ग मजदूरी के बदले में अपनी श्रम शक्ति को समय या उत्पादन की विभिन्न मात्रा में बेचता है। मजदूर वर्ग में वे लोग शामिल हैं जो पूरी तरह से अधीनस्थ भूमिका में हैं। यह आधुनिक उद्योगों, रेलवे और वृक्षारोपण की स्थापना के परिणामस्वरूप भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान उभरा। यह मुख्य रूप से गरीब किसानों और बर्बाद कारीगरों से गठित किया गया था। स्वतंत्र भारत में अन्य सभी वर्गों की तरह श्रमिक वर्ग भी बड़ी मात्रा में बढ़ा है। मजदूर वर्ग के सदस्य अलग-अलग हिस्सों और विभिन्न क्षेत्रों में वितरित है। इस वर्ग का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा गठित किया गया है। इस प्रकार, यह विजातिय और विविध है।

श्रमिक वर्ग में विविधता नगरीय रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों की जटिलता के कारण है। भारत की स्वतन्त्रता के बाद औद्योगिक श्रमिक वर्ग के प्रति सरकार का रवैया काफी अनुकूल रहा है। सरकार द्वारा श्रमिकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई अधिनियम और प्रावधान स्थापित किए गए। स्वतंत्र भारत में मजदूर संघ आंदोलन हुए हैं। हालांकि, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जो घर-आधारित उद्योग में अदृश्य श्रम के रूप में काम करते हैं पर्याप्त सरकारी सहायता के अभाव में, वे समाज के हाशिये पर रहते हैं। उन्हें कम मजदूरी मिलती है और संगठित श्रम शक्ति के लाभों से वंचित किया जाता है। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने उनकी प्रस्थिति को दयनीय बनाया है।

बॉक्स 11.5 नगरीय भारत में वर्ग भेद और महिला कार्य-बल भागीदारी

स्वतंत्रता के बाद के भारत में बढ़ते औद्योगिकीकरण और नगरीकरण को चिह्नित किया गया है जिसके साथ महिलाओं के हाशिए और शोषण के नए संदर्भ उभरकर सामने आए हैं। उच्च और मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए यह एक अलग तरह के आर्थिक क्षेत्र,सेवा क्षेत्र, व्यवसायों आदि में उभरने का संकेत देता है, जिसमें उन्हें पितृसत्ता की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। निजी/स्त्री क्षेत्रों से सार्वजनिक/पुरुष क्षेत्रों के अलगाव पर आधारित इन क्षेत्रों और महिला कार्य-बल की व्यवस्था में उनकी खराब भागीदारी है।

गरीब महिलाओं के लिए नगरीय संदर्भ आधुनिक औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में कदम रखना हैं, जो परिचर पितृसत्तात्मक प्रथाओं के साथ-साथ औद्योगिकीकरण (असमान मजदूरी, प्रवास और आवास) की स्थितियों के रूप में दिखाई देने वाली चुनौतियों के नए रूपों में उद्‌भव का संकेत देते हैं। इसके अलावा, घरेलू-श्रमिकों और घर-आधारित उद्योग में प्रतिभागियों के रूप में नगरीय वातावरण के अनौपचारिक क्षेत्र में समावेषन दिखाई दे रहा है।

बोध प्रश्न 3

I) रिक्त स्थानों को भरकर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें:

a) नगरीय भारत में श्रमिक वर्ग का गठन ..... द्वारा किया जाता है।

ख) ..... सफेदपोश कार्यकर्ता हैं।

ग) आधुनिक शहरों और कस्बों के विकास के साथ ..... का वर्ग विकसित हुआ है।

11.5 प्रभुत्व वर्ग मॉडलः असमानता और परिवर्तन

ऐसे विद्वत्तापूर्ण लेखन हैं जो इंगित करते हैं कि स्वतंत्र भारत तीन वर्गों के प्रभुत्व से चिह्नित है। उनकी व्यावसायिक स्थिति, भूमि का स्वामित्व और आय/धन उन्हें जनता के ऊपर शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक महत्वपूर्ण खंड और आधार देते हैं। अक्सर, ये समूह राज्य के साथ सांठगांठ में आ जाते हैं और विकास के लाभ को लूटने वाले सभी विकास लाभों को प्राप्त करते हैं, जो बाद में उनके लिए निर्धारित होता है। हालाँकि, वैश्वीकरण की शुरुआत ने आर्थिक प्रथाओं में एक प्रतिमान चिह्नित किया है, जो चुनावी लोकतंत्र के साथ-साथ राज्य/सरकार को हाशिए के समूहों के हितों का ध्यान रखने के लिए अनिवार्य बनाता है।

11.5.1 संकल्पनात्मक ढांचा

आजादी के बाद के पहले तीन दशकों में भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास की समीक्षा करते हुए, द पोलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट, (1984) में बर्धन ने तीन प्रमुख मालिकाना वर्गों की पहचान औद्योगिक पूँजीपतियों, कृषि पूँजीपतियों/धनी किसानों और नागरिक और सैन्य नौकरशाही और सभी प्रकार के सफेदपोश कार्यकर्ताओं से जुड़े पेशेवरों के रूप में की, जिन्होंने राज्य की नीति के दायरे और प्रकृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। ये तीन वर्ग भारत में सत्तारूढ़ दल का गठन करते हैं। वे राज्य का उपयोग करके अपने हितों की रक्षा और उसे बढ़ावा देते हैं।

फिर भी, राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यह एक स्वायत्त इकाई है जो न केवल राजनीतिक और कानूनी शक्तियों का प्रयोग करती है बल्कि आर्थिक संसाधनों के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करती है। राज्य के पास बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का स्वामित्व है, लाइसेंस की व्यवस्था और ऋण के आवंटन के माध्यम से निजी विनिर्माण क्षेत्र पर नियंत्रण है, हालांकि, प्रमुख वर्गों ने लगातार राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों से लाभ में हेरफेर किया और लाभ उठाया है। उन्होंने राज्य के संसाधनों को खाली कर दिया, जिससे अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी निवेश दोनों में धीरे-धीरे गिरावट आई और इसके परिणामस्वरूप विकास धीमा हो गया। इस प्रकार, अपने निहित स्वार्थों को पूरा करते हुए, प्रमुख वर्गों के विकास के लिए उपाय करना राज्य के लिए लगभग असंभव बना देता है। उन्होंने गरीबों को विस्थापित करते हुए पूंजीवाद की निष्क्रिय क्रांति पैदा की है। सामूहिक गरीबी, आय की असमानता और संसाधनों के असमान वितरण की दृढ़ता उनकी ताकत और राज्य के साथ उनकी सांठगांठ के संदर्भ में स्पष्ट है।

11.5.2 एक नवीन संकल्पनात्मक ढांचाः निरंतरता और बदलाव

पार्थ चटर्जी के अनुसार 1990 के दशक में, वैश्वीकरण की शुरुआत और राज्य की आर्थिक प्रथाओं में परिवर्तन ने निष्क्रिय क्रांति की संरचना और गतिशीलता में कुछ बदलाव किए।

बॉक्सः 11.6 निष्क्रिय क्रांति

> इतालवी दार्शनिक, एंटोनियो ग्राम्स्की ने 'प्रिज्न नोटबुक' में निष्क्रिय क्रांति की अवधारणा पेश की। यह राज्य में कुलीन-निर्मित (इंजीनियर) सामाजिक-राजनीतिक सुधार से संबंधित है जो पूंजीवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करके प्रमुख वर्गों को मजबूत करता है।
>
> सुदीप्त कविराज (1988) और पार्थ चटर्जी (2008) ने अवधारणा को राज्य निर्माण और उच्च वर्ग की कुशलता और नीतियों को उत्तर औपनिवेशिक भारत में समझाने के लिए फैलाया है।

लाइसेंस व्यवस्था को कमजोर करने , विदेशी पूंजी और उपभोक्ता वस्तुओं के, राज्य की राजकोशीय नीति में बदलाव के साथ आसान प्रवाह और निजी क्षेत्रों में दूरसंचार, परिवहन और बैंकिंग जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों को खोलने के कारण वर्ग प्रभुत्व के ढांचे में संशोधन हुए।

पारंपरिक व्यावसायिक घरानों के साथ बदले हुए परिदृष्य में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्तरराष्ट्रीय कंपनियों को पूंजीवादी वर्ग का गठन करना था। इसके अलावा, जमीनी कुलीन वर्ग की तुलना में कॉरपोरेट पूंजीवादी वर्ग का एक अलग तेवर रहा है। पूंजीवादी वर्ग के संबंध में राज्य की स्वायत्तता संदिग्ध हो गई है क्योंकि पूंजीवादी निवेश को घरेलू और विदेशी दोनों के बीच लुभाने के लिए राज्य सरकारों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। यह सब पूंजीवाद की निष्क्रिय क्रांति की सफलता को दर्शाता है, हालांकि इसके एक नए रूप में।

हालांकि, संगठित पूंजी के साथ-साथ गैर- संगठित पूंजी का विशाल क्षेत्र है, जिसमें किसान शामिल हैं और जो अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा हैं, जो तेजी से पूंजीवादी आर्थिक विकास पर राज्य के ध्यान केंद्रित होने के साथ-साथ हाशिए पर जा रहा है। चुनावी लोकतंत्र की षर्तों के तहत निष्क्रिय क्रांति सरकार के लिए हाशिए की आबादी के लिए अपना प्रबंध स्वयं करना अस्वीकार्य और नाजायज बनाती है। यह उन्हें ''खतरनाक वर्गों'' में बदलने का जोखिम उठाता है। इसलिए, बढ़ती पूंजीवाद के प्रभावों को उलटने के लिए सरकारी

नीतियों की एक पूरी श्रृंखला तैयार की जाती है। संक्षेप में, हाशिए के वर्गों को खाना देना, कपड़ा पहनाना और काम दिया जाना है जो राजनीति की कठिन और अभिनव प्रक्रिया है, जिस पर लोकतंत्र की परिस्थितियों में निष्क्रिय क्रांति का भविष्य निर्भर करता है।

सोचे और करो 3

खुदरा बाजार में कॉर्पोरेट पूंजी के प्रवेश के खिलाफ कई भारतीय राज्यों में आंदोलन हुए हैं। संक्षेप में, पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में घटी उस घटना का वर्णन करें, जिसमें बताया गया है कि कैसे गैर-कॉर्पोरेट क्षेत्र कॉर्पोरेट पूंजी के लिए एक चुनौती बन गया है।

बोध प्रश्न 4

i) स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में किसने प्रभुत्वशाली वर्ग का गठन किया। (1 वाक्य में बताएं)

.....

.....

.....

.....

.....

ii) उन कारणों को संक्षेप में बताएं जिसको प्रमुख वर्ग ढांचे में बदलाव और संशोधन के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

.....

.....

.....

.....

.....

11.6 सारांश

इकाई ने भारतीय सामाजिक वास्तविकता में वर्ग की संस्था और परिणामी आर्थिक पदानुक्रम और विभाजन को परिलक्षित किया है। ग्रामीण और नगरीय संदर्भों में वर्ग आधारित असमानताओं की समीक्षा की गई है।जिसे वर्ग-आधारित असमानता को आय और सम्पत्ति में अंतर के संदर्भ में समझा जा सकता है जो वर्तमान संदर्भ में किसी व्यक्ति की व्यावसायिक स्थिति से निकटता से जुड़ा हुआ है।

जाति के साथ-साथ समकालीन भारतीय संदर्भ में, वर्ग एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरा है। वर्ग की स्थिति और राजनीतिक शक्ति के बीच घनिष्ठ संबंध और प्रभुत्वशाली वर्ग की अवधारणा इस बिंदु को दर्शाती है। हालाँकि, चुनावी लोकतंत्र के मद्देनजर सत्ता और नियंत्रण के लिए वर्ग की प्रस्थिति एक महत्वपूर्ण आधार बन गई है, लेकिन हाशिये के समूहों और निम्न वर्गों की अनदेखी नहीं की जा सकती है।

11.7 संदर्भ

बर्धन प्रणव (1984) द पॉलिटिकल इकोनोमी ऑफ डवलवमेंट इन इंडिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, नई दिल्ली।

बेतेले आन्द्रे, (1966) कास्ट क्लास एण्ड पॉवर, चैन्जिंग पैटर्नस ऑफ स्ट्रेफिकेषन इन तंजौर विलेज, ऑक्सफॉर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, नई दिल्ली।

चटर्जी पार्थ, (2008) डेमोक्रेसी एण्ड इकॉनोमिक ट्रॉन्सफोरमेषन इन इंडिया, इकॉनोमिक एण्ड पॉलिटिकल विकली, वॉल्यूम 43, इष्यू 16,

देसाई, ए आर (1959) रूरल सोशियॉलॉजी इन इंडिया- द इंडियन सोशायटी ऑफ एग्रीकल्चर इकॉनोमिक्स- बॉम्बे।

जोशी, पी.सी. (1974) लैण्ड रिफॉर्म एण्ड एग्रीअन चैन्ज इन इण्डिलया एण्ड पाकिस्तान सिन्स 1947, जर्नल ऑफ पीसेन्ट, पार्ट 1 और 2 ।

जोशी, पी.सी. (1967) प्री एण्ड इंडेपेनडेन्स थींकिंग ऑन एग्रीअन पॉलिसी इकॉनोमीक्स एण्ड पॉलिटीकल वीकली वॉल्यूम 2 ।

कविराज, सुदीप्ता, (1988) ए क्रीटीक्यू ऑफ पैसिव रिवॉल्युषन इकॉनोमिक एण्ड पॉलिटिकल विकली वॉल्यूम 23 इष्यू 16।

कुमकुम सांगरी और सुदेश वैद, (1989) रिकॉसटिंग वुमैन एसैस इन कॉलोनियल हिस्ट्री, नई दिल्ली काली फॉर वुमेन

मैन्सर जोना, (2002) वॉट हैपिन्ड टू लैण्ड रिफॉर्म इन थिकिंग सोशल साइन्स इन इंडिया एसैस इन ऑनर ऑफ एलाइस थॉजनर सुजाता पटेल, जसोधरा बागची और कष्णा राज, नई दिल्ली।

थॉरनर डैनियल, (1956) एग्रीअन स्ट्रक्चर, दिल्ली एल्लाइड पब्लीषर।

11.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न का उत्तर 1

i) रिक्त स्थानों को भरकर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें:

   क) जजमानी पारंपरिक व्यावसायिक दायित्वों/संरक्षक-ग्राहक संबंधों की एक व्यवस्था है।

   ख) किसी व्यक्ति की जाति प्रस्थिति जन्म और वंशानुगत रूप से निर्धारित की जाती है, इसके विपरीत उसकी वर्ग प्रस्थिति लचीली होती है जो सम्पत्ति /आय पर आधारित है और उसे अर्जित किया जा सकता है।

   ग) भारतीय समाज में स्तरीकरण और पद वितरण के आधार के रूप में जाति की तुलना में वर्ग महत्व हाल ही में आया है।

बोध प्रश्न का उत्तर 2

i) प्रारंभिक राष्ट्रवादी औपनिवेशिक कृषि नीति की आलोचना कैसे करते हैं? (3 वाक्यों में व्याख्या करें)

   उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध के बाद से प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने दमनकारी राजस्व प्रणाली सहित भूमि की औपनिवेशिक नीति की आलोचना की थी। दोनों जस्टिस

रानाडे और आर.सी. दत्ता ने औपनिवेशिक राज्य को संस्थागत संरचना, अर्थात् पारंपरिक भूमि संबंधों, जो कि आर्थिक पिछड़ेपन पर सीधा असर डालता है और जिसमें पुनर्गठन के लिए राज्य के प्रबल हस्तक्षेप की आवश्यकता है, की अनदेखी करने के लिए प्रश्न किए । हालाँकि, बाद के राष्ट्रवादियों के विपरीत वे कृषि असमानता के समाधान के लिए पर्याप्त उपाय नहीं सुझा सके।

ii) हरित क्रांति ने कृषि प्रधान भारत में विषमताओं को बढ़ाने में योगदान दिया। (1 वाक्य में स्पष्ट करें)

हरित क्रांति ने पूंजी प्रधान कृषि विधियों और तकनीकों का परिचय दिया और केवल बड़े भू-मालिकों और समृद्ध किसानों को लाभ हुआ, इसलिए भारत में असमानताओं में वृद्धि हुई ।

iii) डैनियल थॉर्नर की कृषि वर्गों के वर्गीकरण की गणना करें।

डैनियल थॉर्नर ने तीन विशिष्ट शब्दों का उपयोग करके कृषि संबंधों का विश्लेषण किया हैः कृषि जमींदारों के लिए मालिक, काम करने वाले कृषकों के लिए किसान (किरायेदारों सहित), और खेतिहर मजदूरों के लिए मजदूर।

बोध प्रश्न का उत्तर- 3

मैं। रिक्त स्थानों को भरकर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें:

a) नगरीय भारत में श्रमिक वर्ग का गठन हस्तचालित और नीलापोष नौकरियों करने वाले श्रमिकों द्वारा किया जाता है।

b) पेशेवर, प्रबंधक, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, नौकरशाह सफेदपोश कार्यकर्ता हैं।

c) आधुनिक शहरों और कस्बों के विकास के साथ छोटे उद्यमियों का वर्ग विकसित हुआ है।

बोध प्रश्न का उत्तर- 4

i) स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में किसने प्रभुत्वशाली वर्ग का गठन किया? (1 वाक्य में राज्य) द पोलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट में बर्धन, (1984) ने औद्योगिक पूंजीपतियों, कृषि पूँजीपतियों/धनी किसानों और नागरिक और सैन्य नौकरशाही और सफेदपोश मजदूरों से जुड़े पेशेवरों को स्वतंत्रता के बाद के तीन प्रमुख वर्गों के रूप में पहचाना।

ii) उन कारणों को संक्षेप में बताएं जिनको प्रमुख वर्ग ढांचे में बदलाव और संशोधन के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

लाइसेंस व्यवस्था को कमजोर करना, विदेशी पूंजी और उपभोक्ता वस्तुओं के राज्य के राजकोशीय नीति में बदलाव के साथ आसान प्रवाह और निजी क्षेत्रों में दूरसंचार, परिवहन और बैंकिंग जैसे कुछ क्षेत्रों में खुलने से वर्ग प्रभुत्व के पहले के ढांचे में संशोधन हुए हैं।

iii) निष्क्रिय क्रांति के राष्ट्र को भी इसमें जोड़ा जा सकता है।